RAJYA SABHA

Tuesday, the 16th August, 1994/25th Sravana, 1916 (Saka)

[The House met at eleven of the clock. **The Deputy Chairman** in the Chair.]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*301. [*The Questioner (Shri Iqbal Singh) was absent. For answer* vide *Col.* 28 *infra*]

Textile Sector Exports

*302. MISS SAROJ KHAPARDE:† SHRI RAMDAS AGARWAL:

Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether an export target of 9 billion US dollars has been set for the textiles sector during the current year;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether Government have recently initiated several steps to boost exports in the textiles sector; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI G. VENKAT SWAMY): (a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) Yes, Sir. The target for 1994-95 represents an increase of 12.8% over the performance during 1993-94. The sector-wise export targets fixed for 1994-95 in dollar/rupee terms are as follows:

(In equivalent Rupee terms)

		In Million US Dollars	Rs. Crores
1.	Readymade Garments (Apparel)	4262.40	13,371.14
2.	Cotton Textiles		
	(i) Cotton Fabrics & Made-ups (Millmade/Powerloom)	1200.00	3,764.40
	(ii) Cotton Fabrics & Made-ups (Handloom)	475.00	1,490.08
	(iii) Cotton Yarn	530.50	1,664.17
	Sub-total (Cotton Textiles)	**2205.50**	**6,918.65**
3	Man-made fibre Textiles	646.00	2,026.50
4.	Silk Textiles	265.00	831.31
5.	Woollen Textiles	231.50	726.22
	Total (Textiles)	**3348.00**	**10502.68**
6.	Handicrafts	1234.00	3,871.06
7.	Jute	110.00	345.07
8.	Coir	45.60	143.05
	GRAND TOTAL	9000.00	28,2333.00

(c) and (d) In order to step up exports of textiles the Government have taken a number of steps which include encouraging exporters to participate in buyer seller meets, fairs and exhibitions; enabling import of capital goods at concessional

†The question was actually asked on the floor of the House by Miss. Saroj Khaparde.

duty for export production; special arrangements for duty-free import of raw materials for export-production; ensuring increased availability of export credit; etc.

MISS SAROJ KHAPARDE: Madam, I would like to know from the hon. Minister whether the Government have conducted any market research or made any assessment regarding particular items of textile products like handicrafts, coir, jute, etc. to find out which items are facing stiff competition in foreign markets, and what specific steps have been taken to boost aggressively, our exports in foreign markets.

श्री जी० वेंकटस्वामी: उपसभापति महोदया, आनरेबल मेम्बर को मैंने डिटेल में स्टेटमैंट दिया है कि हम गवर्नमेंट की तरफ से, मिनिस्टरी की तरफ से एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए क्या-क्या कर रहे हैं। जैसे, "In order to step up exports of textiles, the Government have taken a number of steps which include encouraging exporters to participate in buyer-seller meets fairs and exhibitions...."

MISS SAROJ KHAPARDE: This is my question.

उपसभापति: इन्होंने सवाल किया है कि एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए आपने जो-जो कदम उठाये हैं उसके बारे में बता दीजिए।

MISS SAROJ KHAPARDE: Specifically I asked about handicrafts, coir, and jute.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Handicrafts, Coir, and jute.

श्री जी० वेंकटस्वामी: Market Survey research done by export promotion councils regarding handicrafts, coir and jute वगैरह में पर इसके साथ ही मैं आनरेबल मेंबर को बताना चाहता हूं कि हैंडीक्राफ्ट्स में हमारा एक्सपोर्ट बहुत आगे बढ़ चुका है। 1992 में तकरीबन 1800 करोड़ था इस साल 3,800 करोड़ का टारगेट हमने रखा है और पिछले साल 3,300 तक पहुंच चुके हैं और कम्पीटीशन हैंडीक्राफ्ट्स में ज्यादा नहीं है। आनरेबल मेम्बर को बताना चाहता हूं कि हैंडीक्राफ्टस का एक्सपोर्ट एन्करेजिंग है, खासतौर से यूरोप, अमेरिका, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका में। इस साल एशिया के चंद कंट्रीज में भी हैंडीक्राफ्ट्स को फैलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मेरा ख्याल है हमने जो टारगेट रखा है उस टारगेट से भी आगे बढ़ कर 4 हजार करोड़ तक नेक्स्ट ईयर में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं।

MISS SAROJ KHAPARDE: Madam, I would like to know from the hon. Minister whether the South American countries like Brazil, Chile, Argentina, and Mexico and also the countries of South Africa are proposed to be subjected to aggressive marketing of Indian textile products, and if so, whether the Government proposes to include additional textile products, other than ready-made garmets and sythetic textiles, to the list of extreme focused products for marketing thrust in their exports, and if not, what the reasons are.

Part (b) of my supplementary is whether the garment industry is running short of trained workers, and, if so, what special measures the Government proposes to take to make up the shortage at the earliest.

SHRI G. VENKAT SWAMY: Which workers? Handicraft workers?

MISS SAROJ KHAPARDE: Textile workers. Garment workers.

श्री जी० वेंकटस्वामी: सर, फर्स्ट क्वेश्चन इज, साउथ अमेरिका और साउथ अफ्रीका के बारे में जो क्वेश्चन आनरेबल मेम्बर ने पूछा है हमारी मार्केटिंग के बारे में, टैक्सटाइल एंड अदर टैक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में, इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री से जो संबंधित हैं तो हमारे अब तक दो-तीन डेलीगेशन साउथ अफ्रीका जा चुके हैं। पार्टिक्युलरली हैंडीक्राफ्ट और गारमेंटस के लिये काफी इनकरेजिंग है क्योंकि ये नान-कोटा कन्ट्रीज हैं। ब्राजील और साउथ अमेरिका के जो दूसरी कन्ट्रीज हैं, अर्जेंटीना, चिली वगैरह में काफी इनकरेजिंग मार्केटिनग स्कोप है और मैं समझता हूं कि हमारी मार्केटिंग वहां आगे बढ़ेगी। उसी तरह से साउथ अफ्रीका का भी मार्केट पार्टिक्युलरी बहुत ही इंकरेजिंग है और वहां पर भी हमारे डेलीगेशन जा चुके हैं और अनकरीब में हमारी गवर्नमेंट की तरफ से भी डेलीगेशन जाने वाला है। वे लोग बहुत ख्वाहिश कर रहे हैं, इंडियन टेक्सटाईल इंडस्ट्रीज के जो भी प्रोडक्ट्स हैं, उनकी इनकरेजमेंट की वहां से वायर्स की तरफ से, वहां की गवर्नमेंट की तरफ से भी कोशिश

ी रही है। मैं आनरेबल मेंबर को विश्वास दिलाता हूं कि न दो एरियाज में हमारी मार्केटिंग टैक्सटाइल इंडस्ट्री के नये बहुत इनकरेजिंग है और इसे आगे बढ़ाने की हम कोशिश करेंगे।

पार्ट बी में आपने सवाल किया है उसके संबंध में कहना है कि हमारी टैक्सटाइल इंडस्ट्री का जो गारमेंट सेक्टर है, वह तकरीबन 12 हजार करोड़ रुपये का एक्सपोर्ट कर रहा है। यहां पर कटर्स और स्टिचिंग वर्कर्स की शार्टेज है। इसके लिये हम लोगों ने स्टेप नये हैं। फैशन टैक्नालाजी में अनकरीब में कई फैशन टैक्नालाजी ईसटीच्यूट आने वाली हैं और वहां पर हम वर्कर्स को तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, खासतौर कटिंग और स्टिचिंग के लिये और दूसरे डिप्लोमा कोर्सेज के लिये भी हम कोशिश करेंगे और अनकरीब में शुरू करेंगे।

SHRIMATI JAYANTHI NATARAAN: Madam, the hon. Minister, in his reply laid on the Table of the House, has given certain very encouraging figures. We all know that after the signing of the GATT, one of the areas which is of the great est interest or of the greatest benefit in the area of textile export. The Minister will agree with me that one of the largest markets is the market of the United States.

Madam, recently, two days ago, there was a very disturbing report in the newspapers about how there has been tremendous publicity all over the United States on TV that the Indian rayon skirts were dangerous for use. After that, after the wide publicity on the national television in the United States, the spokesmen of the Government and other apex textile bodies in the United States, held the skirts in their hands and burnt them. I am sure this is an excessive bad publicity for the Indian skirts, as a result of which the import of Indian skirts into the US has been banned.

My question to the hon. Minister is in two parts. One, is the Minister aware of such negative publicity, and what steps are being taken to assure the American public which is one of the largest importing public that the Indian goods are not dangerous?

Secondly, is there any truth in the assertion that these fabrics are inflammable?

Will the Minister take it up with the United States? What is going to happen to the agreements already entered into with the Indian exporters?

The problem would arise in regard to our exports. The question would be as to how much the Indian exporters are going to lose over this and to what extent, in future, our exports would be affected.

श्री जी० वेंकटस्वामी: उपसभापति महोदया, पहला तो सवाल यह है कि आनरेबल मैम्बर ने यह जैसे अमरीका को एक्सपोर्ट के बारे में कहा, यह सही नहीं है क्योंकि हमारा गारमेंट एक्सपोर्ट सब से ज्यादा यूरोपियन यूनियन मार्केट के लिए होता है और अमरीका का सेकेंड नम्बर आता है। यह न्यूज़ बिल्कुल सही है, मिनिस्ट्री इसके ऊपर सीरियसली सोच रही है कि क्या करना चाहिये क्योंकि यहां पर यह गवर्नमेंट की तरफ से नहीं बल्कि एक कमीशन की तरफ से कहा जा रहा है कि बारिक रेयान रहने से जल जाएंगे, खतरा है। इस तरह से आ रहा है। मैं आपकी इनफॉरमेशन के लिए बताना चाहता हूं कि रेयान का उसमें इस्तेमाल होता है और दो तीन साल के अन्दर वहां पर हमारी इस डिज़ाइन की स्कर्टस का बिजनेस बहुत आगे बढ़ा है। दो साल में 30 गुना से ज्यादा हमारा एक्सपोर्ट हुआ है। वहां से ट्रेडर्ज में खलबली मची। कोई चारा नहीं था। पहले उन लोगों ने वहां पर बन्द कराने की कोशिश की, वहां के आफिशियल्ज़ ने कोशिश की कि आप जो भेज रहे हैं यह ठीक नहीं है वगैरह-वगैरह । जब वह ठीक नहीं जमा तो वहां के एक कमीशन की तरफ से डिक्लेयर करवाया गया कि इसमें रेयान बड़ा डेंजरस है। उन्होंने खुद क्लेरीफाई किया है। इससे कोई मरा नहीं है आज तक न वहां और न इण्डिया में और न कहीं और ऐसा हुआ है। इससे कोई खतरा नहीं हुआ है। मिनिस्ट्री की तरफ से उसके ऊपर सारे एक्सपोर्टर्ज़ को बुला कर एक मीटिंग करेंगे कि क्या एक्शन लेना चाहिये और किस तरह से इसको टेक-अप करना चाहिये। ज़रूर हम इस कोशिश में लगे हैं कि मिनिस्ट्री की तरफ से क्या कदम उठाएं।

SHRI JAGESH DESAI: Madam, fifty per cent of our textile exports consist of readymade garments. This is one of the important items of our exports. For the

year 1994-95, the target has been increased by 12.8 per cent over the year 1993-94, whereas the growth in exports in the year 1993-94 was 21 per cent. In this connection, I would like to know from the hon. Minister as to what was the growth in export of readymade garments and textiles in the year 1993-94 compared to the growth in 1992-93. What has been the increase in exports, in percentage terms? Why have you fixed a very low target — 12.8 per cent — for the year 1994-95? Will the hon. Minister enlighten us on this?

Secondly, what would be the effect of this ban on our rayon skirts in the U.S.A.? To what extent would our exports be reduced? of Course, you are going to hold talks, but that would not be sufficient. We have to give a proper answer. We should take it up with the leaders of the U.S.A. because, as I said, this is one of the most important items of our exports. As it was going up by 30 per cent, the vested interests in the U.S.A. have tried to put out this kind of story. How are you going to meet it?

श्री जी० वेंकटस्वामी: उपसभापति, महोदया, ग्रोथ रेट के बारे में आप जानते हैं कि काटन के प्राइसेज़ इनक्रीज़ होने की वजह से यानी प्राइसेज़ भी इनक्रीज़ हुए हैं। इसकी वजह से हमारे ग्रोथ रेट में थोड़ी कमी दिखाई गई है।

SHRI JAGESH DESAI: I would just like to point out. If this is the reason, there is no growth at all because you have to take into account the inflation rate of 10 per cent. If these are the factors, the actual quantity would be much less than what it was in 1993-94. Will the hon. Minister clarify?

श्री जी० वेंकटस्वामी: उपसभापति महोदया, मैं वही क्लेरीफाई करने जा रहा था। मैं बताना चाह रहा था कि लास्ट ईयर और इस साल भी काटन के रेट्स काफी बढ़ चुके हैं। आप जानते हैं कि काटन के रेट्स डबल और ट्रिपल हुए और इण्डिया में आज तक इतने काटन के रेट नहीं बढ़े हैं। इसके बावजूद भी हमने मिनिस्ट्रीज़ की तरफ से ग्रोथ रेट इनक्रीज़ करने के लिए स्टेप्स लिये हैं और हमने करीब टारगेट 28000 करोड़ रुपए के लिए फिक्स किया है। मैं आनरेबल मैम्बर को विश्वास दिलाता हूं कि इस साल ग्रोथ रेट इनक्रीज़ के साथ-साथ हमारा एक्सपोर्ट भी इनक्रीज़ होगा।

इसका मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं। दूसरा, स्कर्ट के बारे में क्वेश्चन आनरेबुल मेम्बर ने किया। अमेरिका के अंदर जो काफी पब्लिसिटी हो रही है। बिल्कुल सही है। इस तरह से पब्लिसिटी की जा रही है कि देखिए अगर पहनेंगे तो जल जाएंगे। यह डर बैठाया जा रहा है पब्लिक में। इस सिलसिले में मैं आनरेबुल मेम्बर को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि गवर्नमेंट की तरफ से और एक बात साफ है कि हमारे एक्सपोर्ट में इससे कमी नहीं होगी। यह करने के बावजूद भी कमी नहीं होगी। अमेरिका का जो कोटा है, यह इस कोटे के बाहर है। कोटे के अंदर नहीं है।

इस टाइप का स्कर्ट अमेरिका के अंदर जो पापुलर हुआ है उससे वहां के ट्रेडर्स घबड़ा गए हैं। घबड़ाकर हौला हवाला लेकर इसको रोकना चाहते हैं। इसको रोकने के लिए जो कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है, हमको क्या करना है मैं आनरेबुल मेम्बर को विश्वास दिलाता हूं कि गवर्नमेंट इमीडिएटली एक्सपोर्ट की एक मीटिंग बुलाएगी कि हमें क्या कदम उठाने चाहिएं। हम इसके ऊपर जाएंगे।

कुमारी सरोज खापर्डे: आप टी०वी० और अन्य मीडिया का उपयोग क्यों नहीं करते हैं इनके प्रोपेगंडा को नलीफाई करने के लिए। न्यूज मीडिया का क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं। अगर अमेरिका इतना सब कुछ करे तो हमें भी अपने मीडिया का उपयोग करना चाहिए।

श्री जी० वेंकटस्वामी: आनरेबुल मेम्बर की एडवाइस को भी हम जरूर जारी रखेंगे।

SHRI MADAN BHATIA: Madam, I would like to ask the hon. Minister only two short clarifications. First, what has been the annual value of export of skirts to the United States in the last one year? Second, before this ban was imposed, I believe there must be a lot of skirts already in transhipment. What will happen to those transhipped skirts, the value of which may be running into crores, when they reach the shores of the United States? I would like to know whether this question is going to be sorted out, because if their export is not to be allowed in view of this ban, the Indian exporters are going to suffer los-

ses, which I believe may run into crores of rupees.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I do not think they would have anticipated that the skirts are going to be burnt and banned in America. So, they would have specifically kept it separate. I think it must be in bulk.

SHRI G. VENKAT SWAMY: The annual value of about Rs. 300 crores और जो एक्सन के बारे में कहा है वह मैं पहले ही कह चुका हूं।

उपसभापति: उनका कुछ यह सवाल था मंत्री जी कि कुछ उनका इंश्योरेंस वगैरह है जो पहले से शिपमेंट हो गया है। That will not be affected by this ban. The ones which are in transit, the ones which have already been.....

श्री जी० वेंकटस्वामी: दो रोज पहले यह न्यूज आई है। दो रोज हालीडे था। आज तो वार्किंग डे शुरू हुआ है। अब मैं पता लगाऊंगा और आनरेबुल मेम्बर को बताउंगा।

श्री एस०एस० अहलुवालिया: उपसभापति महोदया, सर्कट के इस मामले को मद्देनजर रखते हुए मैं जानना चाहूंगा क्योंकि हमारे देश में महात्मा गांधी ने मैनचेस्टर के बने हुए कपड़ों का विरोध करते हुए एक आंदोलन चलाया था। जहां कहा गया था कि विदेशी कपड़ों को जला डाला जाए। किसी भी कंट्री के मैनुफैक्चरर को अगर इकनामिकली वीक करना है या उसकी सेलिंग कॉम्पेटिशियलिटी को कम करना है तो उसका सही तरीका इस कपड़े के बारे में कुप्रचार करना होता है। तो भारतीय वस्त्र का भी कुप्रचार अमेरिका में हो रहा है। यह अमेरिका के लोग कर रहे हैं या अमेरिका में भारत के साथ कंपटीशन में कपड़े बेचने वाले — जिसमें कि पाकिस्तान भी है, वे लोग करा रहे हैं, इसके बारे में आपने कोई इंक्वायरी करने की कोशिश की है कि नहीं?

उपसभापति: करेंगे।

श्री एस०एस० अहलुवालिया: इसकी इंक्वायरी करने की जरूरत है। महोदया, यह इसलिए मैं कह रहा हूं कि कुछ लोगों ने बासमती चावल में भी इसी तरह देखा है। कुछ लोग बासमती चावल में जो अपने आपको पायनियर समझते थे आज आहिस्ता आहिस्ता उसमें पिछड़ रहे हैं क्योंकि उसमें अभी एक एक्सट्रा अरोमा एड करके हमारे बासमती चावल को डिफीट करने की कोशिश की गयी है।

इस कपड़े के उद्योग में भी ये सभी इस तरह का कुप्रचार कर सकते हैं। तो "गैट" का जो समझौता हुआ है और उसमें जो कपड़े के सारे नियम आए हैं, अगर उसके तहत कल को भारतीय वस्त्र पहनने का एक बहिष्कार डवलप्ड कंट्रीज में शुरू होता है तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं या "गैट" एग्रीमेंट के तहत हमें कोई रिलीफ मिल सकती है या हम अपने इंटरेस्ट को प्रोटैक्ट करने के लिए पूरी तरह से काबिल हैं कि नहीं, मंत्रीजी यह बताने की कृपा करें?

श्री जी० वेंकट स्वामी: उपसभापति जी, आनरेबल मेंबर का क्वेचन बिल्कुल सही है। पाकिस्तान का इसमें हाथ है कि नहीं, यह मैं नहीं कह सकता, मगर यह जरूर कहूंगा कि कार्पेट इंडस्ट्री में हमारा जितना भी कार्पेट एक्सपोर्ट हो रहा है, उसमें हमारा कंपटीटर पाकिस्तान भी है और दूसरे देश भी हैं। उसमें हमारी कुछ बदकिस्मती है कि जो हिंदुस्तान से आय०एल०ओ० में रिप्रिजेंट करते हैं, यह लोग प्रचार करते हैं कि कार्पेट जमीन में बिछाकर उस पर खून डाला जाता है और यह बच्चों का खून है। इस किस्म के प्रचार के चक्कर में आना कि हिंदुस्तान का कार्पेट बच्चों के द्वारा बनाया जा रहा है, सहीं नहीं है। जैसेकि कल प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि चाइल्ड लेबर के एबोलीशन के लिए पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस पर एक्शन ले रही है। उस उद्योग में बच्चे अब बहुत कम हो चुके हैं। इस सिलसिले में मैं डिटेल्ड रिपोर्ट आनरेबल मेंबर को दूंगा। इस बारे में मैं कल ट्रेडर्स के साथ बातचीत के बाद नतीजे पर आऊंगा और आपको सही रिप्लाय दे सकता हूं क्योंकि अभी उनसे बात ही नहीं हुई है और वहां से भी अभी पूरी तरह इनफॉर्मेशन नहीं आयी है। वह सब मैं कलैक्ट कर रहा हूं और उसके बाद ही मैं यह इनफॉर्मेशन आपको पास करूंगा।

SHRIMATI CHANDRIKA ABHINANDAN JAIN: Thank you, Madam. The hon. Minister has given the figures of the export target for 1994-95 and he has stated that there is an augmentation of 12.8 per cent over the performance during the year 1993-94. As far as the export of cotton yarn is concerned, the figures suggest that there is a projection of something like $ 530.50 million as export target and in terms of 1,664.17 crores. As I understand there is

a ban on export of cotton yarn. I find there is an anomaly.

I would like to know from the hon. Minister, whether there is any proposal with the Government to remove the ban on export of cotton yarn. There is a lot of hardship being faced by the manufacturers of cotton yarn. I would like to know from the hon. Minister whether he is going to lift the ban on cotton yarn.

Part (b) of the question is, there is a lot of export obligations on the part of manufacturers who have imported machinery. They have stated that they are going to pay the amount by way of export obligations. When the Government puts a ban on export of cotton yarn, how do they expect these manufacturers to fulfil their export obligations?

श्री जी॰ वेंकटस्वामी: उपसभापति महोदया, ऑनरेबल मेंबर का क्युचन है कि कॉटन यार्न को क्यों नहीं बैन से निकला जाता है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि जो कोटा उनको दिया गया था, वह छः महीने के अंदर उन्होंने पूरा कर लिया है, अब और मांग रहे हैं। अगर इस वक्त यार्न और दिया जाए तो आप जानते हैं कि देश के अंदर कॉटन रेट्स बढ़ने की वजह से पर्टीकुलरली हैडलूम यार्न की कीमत बहुत बढ़ चुकी है। इसी तरह से अगर यार्न को एक्सपोर्ट के लिए दिया जाए तो डॉमेस्टिक कपड़े के साथ-साथ हैडलूम वीवर्स के लिए भी मुश्किल होगी और इस कपड़े को पहननेवाले हमारे गरीब लोगों को भी मुश्किल होगी। इसकी हमने बहुत कोशिश की है और इनको इस साल जो हंड्रेड मिलियन के॰जी॰ का कोटा दिया गया था वह छः महीने के अंदर उन्होंने पूरा कर लिया है और इस साल और मांग रहे हैं। उपसभापति महोदया, कॉटन की पोजीशन स्टडी की जा रही है, उसके बाद नेक्स्ट इयर ...(**व्यवधान**)...

SHRI VAYALAR RAVI: Handloom interests will suffer. *(Interruptions)*. Don't do that.

श्री जी॰ वेंकटस्वामी: कोशिश की जा रही है। स्टडी तो करें कि कितना कॉटन यार्न हमारे पास है, कितना हैंक यार्न हमारे पास है। इसके आंकड़े आने के बाद सोचा जाएगा।

SHRIMATI CHANDRIKA ABHINANDAN JAIN: What about the export obligation? *(Interruptions)*.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Question No. 303.

Incremental Non Food Credit

*303. DR. SHRIKANT RAMCHANDRA JICHKAR: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) what is the present incrementa non-food credit excluding export ratio t deposit ratio for the scheduled bank under the busy season credit policy;

(b) the banks which have exceeded th ratio for two successive fortnights durin the current year; and

(c) whether they have faced an auto matic reduction in refinance limits?

THE MINISTER OF STATE IN THI MINISTRY OF FINANCE (SHRI M.V CHANDRASHEKHAR MURTHY): (a to (c) Reserve Bank of India (RBI) ha reported that the present, there is n stipulation regarding incremental net-non food credit (excluding export credit) de posit ratio for scheduled commercia banks.

DR. SHRIKANT RAMCHANDR JICHKAR: Madam, the Reserve Bank c India has reported that there is no stipu lation for this ratio and the hon. Ministe has believed the Reserve Bank. I woul like to draw the attention of the hon Minister to pages 50, 52 and 198 of th latest Annual Report of the Reserv Bank of India. In this latest Annua Report of the Reserve Bank of Indi they have discussed this ratio. The Re serve Bank of India has projected thi ratio even for June, 1994. Even in th latest Economic Survey—I would like t draw the attention of the hon. Minister t pages 38 and 39 — which was laid befor Parliament during this year, you hav discussed this ratio. How is it that th Reserve Bank has reported that there i no stipulation and you do not maintai this ratio? I would like the hon. Ministe to react to this. I would also like to kno what react to this. I would also like t know what action he would take on th